



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2015/ज्येष्ठ 19, 1937

No. 219]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2015/JYAISTHA 19, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2015

सं. टीएमपी/23/2013-एमबीपीटी. – महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मुम्बई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मुम्बई पत्तन न्यास के दर मानों में धारा 2.16 – पत्तन देय राशियों के नीचे अंतर्गत टिप्पणी संख्या 9 में संशोधन को संलग्न आदेश के अनुसार, अनुमोदित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/23/2013-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास

.....

आवेदक

कोरम:

- (i) श्री टी एस बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई, 2015 के 15वें दिन पारित)

प्राधिकरण ने मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से उसके दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर मामला संख्या टीएमपी/23/2013-एमबीपीटी में दरमान अधिसूचित करते हुए 2 जनवरी, 2015 को आदेश पारित किए थे। यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग 3, खण्ड 4) दिनांक 19 जनवरी, 2015 के राजपत्र संख्या 19 में अधिसूचित किया गया है। एमबीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं को संशोधित दरमान हमारे 20 जनवरी, 2015 के पत्र द्वारा संसूचित कर दिए गए थे।

2. इस पृष्ठभूमि में, एमबीपीटी ने अपने 1 अप्रैल, 2015 के पत्र में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित निवेदन किया:

- (i) एमबीपीटी ने अपने 11 नवम्बर, 2014 के पत्र संख्या एफए/एसीसी/201/10196, के साथ 5 सितम्बर, 2014 के टीआर संख्या 130 की प्रतिलिपि भेजते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को धारा 2.16 पत्तन देय राशि, अध्याय 2, पोत संबंधित प्रभारों के प्रस्तावित एसओआर (महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को 20 जून, 2013 को प्रेषित) के नीचे दिए गए क्रमांक 9 की टिप्पणी को विलुप्त करने और उसे संशोधित प्रस्तावित टिप्पणी क्रम संख्या 9 से प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया है।
- (ii) यह देखा गया है कि उक्त संशोधन दरमानों में अनुमोदित नहीं है। विस्तृत आदेश में उसे हटाये जाने के लिए औचित्य भी नहीं दिया गया है। स्थिति स्पष्ट की जाए।

3.1 एमबीपीटी द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में, जैसा कि ऊपर दिया गया है, उसके दरमानों के सामान्य संशोधन से संबंधित कार्यवाही के दौरान मामले का परीक्षण किया गया और एमबीपीटी द्वारा किए गए निवेदन के संदर्भ में विश्लेषण किया गया।

3.2 धारा 2.16 के नीचे टिप्पणी संख्या 9-एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों में पत्तन को देय राशि को नीचे पुनः उद्धरित किया जा रहा है :-

“उन पोतों की पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशि नहीं उगाही जाएगी जिन्हें नौसेना अभ्यास के कारण अपना लदान/उतरायी पूरी किए बिना पत्तन सीमाओं से बाहर जाने को बाध्य होना पड़ा था।”

3.3 अगस्त, 2013 के अपने आरम्भिक प्रस्ताव, के साथ-साथ, सितम्बर, 2014 के संशोधित प्रस्ताव में, एमबीपीटी ने अपने तत्कालीन प्रस्तावित प्रारूप दरमानों में उक्त टिप्पण में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था, इस प्रकार उक्त वर्णित टिप्पणी को बनाये रखना प्रस्तावित किया।

3.4 लेकिन, बाद में, एमबीपीटी ने अपने 11 नवम्बर, 2014 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निवेदन किया:-

- (क) न्यासी मंडल 05.09.2014 के टीआर संख्या 130 के द्वारा जहां पोतों को पोत एजेंटों और पोतों को किन्ही अन्य कारणों से, जिनके लिए वे उत्तरदायी नहीं होते, बाहर जाना आवश्यक हो जाता है, तो उनके पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशियों की उगाही के लिए, दरमानों में प्रावधानों के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पत्तन द्वारा बोर्ड के संकल्प की एक प्रति भेजी गई है।

- (ख) धारा 2.16, पत्तन को देय राशियां- अध्याय-2, प्रस्तावित दरमान के पोत संबंधी प्रभारों के अंतर्गत क्रमांक 9 पर टिप्पणी अनुमोदन के लिए 20 जुलाई, 2013 को महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को भेजी गई थी, का विलोपन कर दिया जाए और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-
“पोतों को उतरायी/लदान प्रक्रिया पूरी किए बिना पत्तन सीमाओं से बाहर जाने को बाध्य किए जाने के पश्चात और उसी जलयात्र के दौरान पोतों के पत्तन में पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशियां उगाही नहीं जाएंगी। जब :

- (क) यदि नौसेना अभ्यास किया जा रहा हो यानी सुरक्षा की दृष्टि से और पोत को लंगरगाह के बाहर स्थानांतरित करना।
- (ख) यदि पोत को, अन्य यात्री पोत को स्थान देने के लिए, लंगरगाह के बाहर स्थानांतरित करना।
- (ग) पोत के प्रवेश करने के पश्चात पोत के लिए कोई उपयुक्त गहरा भारवहन लंगरगाह न होना और उसे बाहरी लंगरगाह पर जाने को बाध्य होना पड़ा।
- (घ) क्रमिक घाट अथवा जलमार्ग में निकर्षण कार्य किए जाने के कारण पोत को बाहर जाने के लिए बाध्य होना।

- (ड) यदि पोत को प्रचालन कठिनाइयों जैसे पोत-परिवहन प्रचालन के लिए आवश्यक एमबीपीटी फ्लोटिंग क्राफ्ट उपलब्ध न होना अथवा ज्वार में परिवर्तन या लॉक-गेट का खराब होना आदि के कारण लंगरगाह से बाहर जाना।
- (च) यदि पोत को गहरा भारवहन लंगरगाह उपलब्ध न होने के कारण बाहरी लंगरगाह पर जाना पड़े।
- (छ) सुरक्षा की दृष्टि से, जिनके लिए पोत उत्तरदायी नहीं होते, कोई अन्य प्रचालन कारण।

3.5 फिर भी, एमबीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव में इस पहलु पर अनजाने ही विचार नहीं किया जा सका।

4.1 एमबीपीटी द्वारा भेजे गए बोर्ड टिप्पण की प्रति से और कि, मुम्बई और न्हेवा शेवा शिप एजेंट एसोसिएशन (एमएएनएसए) द्वारा एमबीपीटी के समक्ष उठायी गई आपत्तियों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि, एमबीपीटी द्वारा अपने बोर्ड के समक्ष दरमानों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। जहां तक पोत के पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशियों की वसूली का संबंध है यह इस प्रकार की जाए कि अतिरिक्त देय राशि सभी मामलों में न वसूली जाए, जहां पोतों को पोत एजेंटों और पोतों के अधिकार के बाहर के कारणों से बाहर जाना आवश्यक हो जाता है, बोर्ड ने उक्त संशोधन को अनुमोदित कर दिया है, ताकि पत्तन की सुविधाओं के लिए पत्तन से बाहर जाकर पोतों के पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशियों से छूट प्रदान की जा सके।

4.2 प्रस्तावित आशोधन, पोतों के पुनः प्रवेश के मामले में पत्तन देय राशि उगाहने में स्पष्टता लाता है। प्रस्तावित आशोधन व्यापार हित में है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर और एमबीपीटी द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर, यह प्राधिकरण धारा 2.16 – पत्तन को देय राशियों के अधीन टिप्पणी संख्या 9 के आशोधन को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

5. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए और सामुहिक ज्ञान के आधार पर, यह प्राधिकरण एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों में धारा 2.16 – पत्तन देय राशियों के नीचे वर्तमान टिप्पणी संख्या 9 को निम्नलिखित टिप्पण से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान करता है :-

- “9. पोतोंको उतरायी/लदान प्रक्रिया पूरी किए बिना पत्तन सीमाओं से बाहर जाने को बाध्य किए जाने के पश्चात और उसी जलयान के दौरान पोतों के पत्तन में पुनः प्रवेश पर पत्तन को देय राशियां उगाही नहीं जाएंगी। जब :
- (क) यदि नौसेना अभ्यास किया जा रहा हो यानी सुरक्षा की दृष्टि से और पोत को लंगरगाह के बाहर स्थानांतरित करना।
 - (ख) यदि पोत को, अन्य यात्री पोत को स्थान देने के लिए, लंगरगाह के बाहर स्थानांतरित करना।
 - (ग) पोत के प्रवेश करने के पश्चात पोत के लिए कोई उपयुक्त गहरा भारवहन लंगरगाह न होना और उसे बाहरी लंगरगाह पर जाने को बाध्य होना पड़ा।
 - (घ) क्रमिक घाट अथवा जलमार्ग में निकर्षण कार्य किए जाने के कारण पोत को बाहर जाने के लिए बाध्य होना।
 - (ड) यदि पोत को प्रचालन कठिनाइयों जैसे पोत-परिवहन प्रचालन के लिए आवश्यक एमबीपीटी फ्लोटिंग क्राफ्ट उपलब्ध न होना अथवा ज्वार में परिवर्तन या लॉक-गेट का खराब होना आदि के कारण लंगरगाह से बाहर जाना।
 - (च) यदि पोत को गहरा भारवहन लंगरगाह उपलब्ध न होने के कारण बाहरी लंगरगाह पर जाना पड़े।
 - (छ) सुरक्षा की दृष्टि से, जिनके लिए पोत उत्तरदायी नहीं होते, कोई अन्य प्रचालन कारण।”

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(108)]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th June, 2015

No. TAMP/23/2013-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Note no. 9 under Section 2.16 – Port Dues in the Scale of Rates of Mumbai Port Trust with regard to proposal received from Mumbai Port Trust, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/23/2032-MBPT

Mumbai Port Trust

.....Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of May 2015)

This Authority has passed an Order dated 2 January 2015, notifying the Scale of Rates in case No.TAMP/23/2013-MBPT relating to the proposal received from the Mumbai Port Trust (MBPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR). This Order has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 19 January 2015 vide Gazette No.19. The revised Scale of Rates has been communicated to the MBPT and the concerned users vide our letter dated 20 January 2015.

2. In this backdrop, the MBPT vide its letter dated 01 April 2015 has, interalia, made the following submission:

- (i). The MBPT vide its letter No. FA/ACC/201/10196 dated 11 November 2014, a copy of TR No. 130 of 5 September 2014 had requested TAMP to delete the note at Sr. No. 9 under section 2.16 port dues, chapter II, vessel related charges of proposed SOR (forwarded to TAMP on 20 June 2013) and replace the same by revised proposed notes at Sr. No. 9.
- (ii). It is seen that the said amendments is not approved in the revised SOR. Justification for exclusion of the same is also not given in the detailed Order. The position may be clarified.

3.1. With regard to the submissions made by MBPT as brought out above, the matter has been examined and analysed with reference to the submissions made by the MBPT during the proceedings relating to its general revision of its Scale of Rates.

- 3.2. The Note no. 9 under Section 2.16 – Port Dues in the existing Scale of Rates of MBPT is reproduced below:
“No port dues shall be levied on the vessels re-entering the port after being forced to go out of the port limits before completing its discharge / loading, when naval exercise is undertaken.”

3.3. In its initial proposal of August 2013 as well as in the revised proposal of September 2014, the MBPT in its then proposed draft Scale of Rates had not proposed to make any changes in the above mentioned note and had, thus, proposed to retain the above mentioned note.

3.4. However, subsequently, the MBPT *vide* its letter dated 11 November 2014 had, interalia, made the following submissions:

- (a). Board of Trustees *vide* TR No.130 of 05.09.2014 has accorded sanction for proposal for amending the provision in Scale of Rates for recovery of re-entry of Port dues where the vessels are required to move out for reasons not attributable to the vessel agents and vessels. A Copy of the Board Resolution has been furnished by the Port.
- (b). The note at Sr.No.9 under Section 2.16 Port Dues, Chapter II, Vessel Related Charges of proposed SOR, forwarded to TAMP on 20.07.2013 for approval may be deleted and replace the same with the following:
 “No port dues shall be levied on the vessels re-entering the port after being forced to move out of the port limits before completing its discharge/ loading operation and in the same voyage when,
 - (a). If the Naval exercise is undertaken i.e. for safety consideration and vessel is shifted to outer anchorage.
 - (b). If the Vessel is shifted to outer anchorage to accommodate another passenger vessel.
 - (c). No suitable deep draft anchorage is available for the vessel after entering the port and forced to go to at outer anchorage.
 - (d). If the vessel was forced to move out due to dredging work carried out at respective berth or channel.
 - (e). If the Vessel is moved to outer anchorage due to operational difficulties such as non-availability of MBPT floating crafts required for shipping operation or change of tide or non-functioning of lock gates etc.
 - (f). If the Vessel is shifted to outer anchorage as deep draft anchorage was not available.
 - (g). Any other operational reasons for safety consideration which are not attributable to the vessel.”

3.5. However, this aspect was inadvertently not dealt with in the general revision proposal of MBPT.

4.1. From the copy of the Board Note furnished by the MBPT, it is seen that based on the objections raised by the Mumbai and Nhava Sheva Ship Agents Association (MANSA) before the MBPT, a proposal was placed by MBPT before its Board to amend the provisions of SOR as regards norms for recovery of Port Dues on re-entry of vessel in such a way that additional port dues are not recovered in all cases where the vessels were required to be moved out for reasons not attributable to the vessel agent and vessel. The Board is seen to have accorded approval to the above mentioned modification, so as to grant exemption from port dues for re-entry of vessels moved out of the port limits for port's convenience.

4.1 The proposed modification gives clarity in the levy of port dues incase of re-entry of vessels. The proposed modification would be in the interest of the trade. In view of this position and based on the justification furnished by the MBPT, this Authority is inclined to approve the modification to the Note no. 9 under Section 2.16 – Port Dues, as proposed by the MBPT.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval to replace the existing note no. 9 under Section 2.16 – Port Dues in the existing Scale of Rates of MBPT with the following note:

- “9. No port dues shall be levied on the vessels re-entering the port after being forced to move out of the port limits before completing its discharge/ loading operation and in the same voyage when,
 - (a). If the Naval exercise is undertaken i.e. for safety consideration and vessel is shifted to outer anchorage.
 - (b). If the Vessel is shifted to outer anchorage to accommodate another passenger vessel.
 - (c). No suitable deep draft anchorage is available for the vessel after entering the port and forced to go to at outer anchorage.

- (d). If the vessel was forced to move out due to dredging work carried out at respective berth or channel.
- (e). If the Vessel is moved to outer anchorage due to operational difficulties such as non-availability of MBPT floating crafts required for shipping operation or change of tide or non-functioning of lock gates etc.
- (f). If the Vessel is shifted to outer anchorage as deep draft anchorage was not available.
- (g). Any other operational reasons for safety consideration which are not attributable to the vessel.”

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2015 (108)]